NEWS in NUMBERS

31.40 रजिस्ट्री ठनी
लखनऊ की संपत्तियों, उपभोक्ता सेवाओं और बैंकों के लॉकर्स दिसंबर तिमाही सर्कल दरमेंट दर लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस

15 वॉल अभियान
अभियान को प्रदेश के दर किले में बंधी 'लाई बालाड़ मंदिरा', 150 पौधों के रोपण से कार्यक्रम लोगों का दिया जागरूक संदेश.

39 हुडन लिस्ट
लखनऊ कमीश्नरी सभी हुडन लिस्ट में शामिल मकिलाओं की कुल संख्या, सर्वाधिक टेक्स की शिकायें लखनऊ कमीश्नरी टीम लेकर मतदीपावरण करेगी.

1,741 स्वदेश वापसी
भारतीयों को म्यांमार-थाईलैंड सीमा के समीपवर्ती सैन्य केंद्रों से सकुशल भारत सुरक्षित वापस, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी.

2025 अमेरिका डिपोर्टेशन
अमरीकी ने भारतीय 2026 के बीच अमेरिका ने 2,414 भारतीयों को किया निर्वासित, राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने दिया लिखित जवाब.

'नहीं टूटेगा छात्रों का भरोसा'

अभी रिपोर्ट दिल खोले, छात्रों व्यवस्था को अपोजेसाइट बताकर की दिल में बड़ा कटल

लोकसभा के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा


संसद में बिल पर हलका करता विपक्ष

NEW DELHI (30 July): पेपर लीक, परीक्षा नकल, हजारोंकी गड़बड़ियों और परीक्षा एजेंसियों को कठघरे में खड़ा करने के विपक्ष के बीच गुरुवार को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्टिविटीज बिल, 2026 पर जोरदार बहस हुई. सरकार ने इसे परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और मल्टीमेंट बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे महज 'प्रतीकात्मक' कदम देते हुए कहा कि जिसे कानून बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसके खुद के दामन पर सवाल हैं. चर्चा के बाद ध्वनिमत से विधेयक पारित हो गया है और उसके बाद राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हुई. इस चर्चा के दौरान कानून मंत्री जे पी नड्डा ने जवाब दिया.

क्या है एंटी पेपर लीक बिल?

सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया है. इसका उद्देश्य NEET, UPSC, SSC, रेलवे, IBPS और NTA जैसी प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक, डिजिटल धोखेबाजी और संगठित नकल पर सख्ती से रोक लगाना है. अधिकारिक प्रोसेसिंग में पेपर लीक रैकेटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जांच और ट्रायल में तेजी, दोषियों को उम्रकैद के प्रावधान व्यापक पैमाने पर हेरफेर करने वाले संगठित गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं.

साथ ही, परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल-केंद्रित बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है. सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा प्रणाली में छात्रहितैषी सुधार और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा.इसके लिए जरूरत प्रयास किये जा रहे हैं

सड़क और सुप्रांत विवेदी ने किया पलटवार

सदन के नेता और भाजपा प्रवक्ता लेखी चंद्रा ने छात्रों की हिम्मती को सलाम करते हुए कहा कि ऐसे कड़ाम सलाम को विपक्ष और उनके नेता कर सकते हैं. चंद्रा ने कहा कि सभी सहमती को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सदन देने चाहिए. भाजपा सांसद सुब्रांत विवेदी ने भी अपने के आरोपों को खारिज किया.

सदन ने की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

राज्यसभा में मुलाकात को पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्टिविटीज बिल, 2026 पर चर्चा होनी थी. लेकिन सदन में सबसे ज्यादा सवाल मनु स्मृति को लेकर हुई. सर्वोच्च अदालत और नेता लोकसभा नलिनकुट्टी आगे ने विपक्ष पर बोलते हुए मनु स्मृति का हवाला दिया.

नकल माफिया पर होगी कड़ी चोट

सरकार ने पेटीएम सभी डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार उन सभी छात्रों के जिनकी भी उनके हो गड़बड़ी के डी 'Zero Tolerance' की नीति पर काम कर रही है. उनके अनुसार यह संशोधन लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा करेगा और भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत करेगा. सरकार ने कहा कि पेपर लीक और नकलीदार-नेटवर्क को अब सामान्य अपराध नहीं बल्कि संगठित अपराध की तरह देखा जाएगा. विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि परीक्षा से जुड़े होने का साबित होने पर 3 से 10 वर्ष तक की जेल, 50 लाख रुपये तक जुर्माना, आर्थिक संगठित गिरोहों के मामलों में दोषी के मामले में 5 वर्ष की कारावास और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

निर्मिटाज सिंह के बयान पर भी छिड़ा संग्राम

सीपीएम सांसद निर्मिटाज सिंह ने भी सदन को हिलाने का आरोप लगाई और इसे गलत बताया. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने निर्मिटाज सिंह के विवादास्पदनोकी पुरुष का दी. सदन में सभी दो दल शोर-शराबा और आरोप-प्रत्यारोप बराबर नहा. सांसदों दवारा इस शोर-शराबे और लौक रोकने वाला विधेयक था. सांसदों के शोर-शराबे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. अंत में नड्डा ने कहा कि यह बिल छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और इसे जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर है और इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

परीक्षीजन पर क्या बवाल?

- 3 अब बाद भी इनमीट की डा नहीं है. कि सरकार इसी बावजूद संसद में निर्धारित डिसिमिटेशन बिल देश लोगों.
- सांसदीय इस बिल को अभी रिपोर्ट नहीं दिया गया है. लोकसभा में डिसप्रशन 548 मिनिटिस नोट है.
- पैनल सरकार के परीक्षीजन विधेयक, 2026 के तहत देश भर में 3 से 5 वर्ष तक के लिए अदालत 816 नोटों जमने का प्रस्ताव पड़ा गया है। 650 पेपर्स छात्रों सेक्स्ट्रा दिया जाई नहीं सो।.
- कुल नहीं अभिप्राय यह ने संसद में लोगों का कि दक्षिण भारत के राज्यों का डिसिमिटेशन हम नहीं होना, क्योंकि उनकी नोटों भी घटेगी, उदहारण के तौर पर तमिलनाडु की सीटें 39 से 59, कर्नाटक की 28 से 42, आंध्र प्रदेश की 25 से 38, तेलंगाना की 17 से 26 और केरल की 20 से 30 होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से घटकर 63 रह जाएंगी।
- जिला, खलवाट डिसिमी राज्यों के लोगों ने प्रशासन लोहाई कि अन्यायपात के आधार पर होने वाले परिसीमन से उत्तर भारत की नोटें अनिवार्यता असिंत कटौती और दक्षिण के राज्यों का हाथ पड़ जायेगा है.

कोयंबटूर ब्लास्ट में 3 राज्यों में रेड

तमिलनाडु, तलंगाना और तेलंगाना के 16 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी

NEW DELHI (30/JULY): 2022 के कोयंबटूर कार बम धमाके से जुड़े टेरर फंडिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लिया. एजेंसी ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुल 16 जगहों पर एक साथ रेड की. छापेमारी चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद और मुंबई में उन लोगों के ठिकानों पर की गई, जिनके इस नेटवर्क से जुड़े होने का शक है. यह जांच एनआईए की दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही है.

फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट से जुड़ाव पैन

ईडी ने सामने आया कि आरोपियों ने असली कोविशील्ड के लिए देय शुल्क के दो बड़े फर्जीवाड़े किए. पहला, कोविड-19 के दौरान जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाना लोगों से पैसे वसूले गए. दूसरा, सोसाइटी कमीशन के नाम पर ट्रेनिंगस और फर्जी बिलों के जरिए फंड इकट्ठा किया गया.

करट्रस्पांस से जुड़कर दर्ज तलिश

एजेंसी को लगे के मुताबिक, आरोपियों समन्वयन अनेक मुलेन बनाए 12 आरोपित सोसाइटी असली सर्टिफिकेट के अधिकारियों और अधिकारियों सर्वर से शामिल हुए थे. इसी तरह कोयंबटूर-चिन्नाती नोड को और ट्रेनिंग सिस्टम तक और बाद में उन्होंने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के समर्थन में बनाने की साजिश रची. मामले में अब तक 11 लोगों के खिलाफ अभियोग दाखिल किया जा चुका है. जांच एजेंसियों के अनुसार, रेड के दौरान अहम डिजिटल सबूत और अवैध लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं. जांच एजेंसी अब इन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

ट्राई-सर्विस विमेन टीम सम्मानित

NEW DELHI (30 July): एयर मार्शल राजश्री सिंह ने गुरुवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की तीनों महिला अधिकारियों को सम्मानित किया. इन अधिकारियों ने देश के पहले महिला सुधार ट्राई-सर्विस संयुक्त अभियान 'समुद्र शक्तिवया' को आईएनएस त्रिशंकु से लीडर का सफलतापूर्वक पूरा किया. यह अभियान के अनुसार, महिला दल ने 314 दिनों में कुल महासागरों में करीब 25,500 समुद्री मील की यात्रा पूरी की. सम्मान प्रेस ने इसे नारी शक्ति, साहस और ट्राई-सर्विस एकता का ऐतिहासिक उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के युवाओं, खासकर महिलाओं को कई रोमांचक करने को प्रेरणा देती. महिला अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए, बताया कि अडिग नौसेना और लंबे चरण के कठिनतम दौरानके और चुनौतीपूर्ण हालातों को कैसे पार किया. इस दौरान उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा किया और विभिन्न देशों के नौसैनिकों के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया.

ममता ने चुनाव आयोग से जल्द जांच मांगी

KOLKATA: 'जलमें तुलकुल' मामले में चल रही जांच के बीच मतदाता सूचियों में सुधार आयोग की एक विशेषज्ञ प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पुट को बार-बार समय दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. ममता ने प्रशासन अधिकारियों से अपील की कि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम न काटें. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था की तरह काम करना चाहिए.

iPOLL
क्या आपको लगता है कि जिलों के (RSB) द्वार पेटीएम ईमेल्ट्स केस को बंद करने का फैसला सही था?
85% हां, निकायों का फायदा होगा शामिल
इसमें डिजिटल मीडिया पर असर होगा
आज का सवाल
क्या केवल से दीक्षी जिले में किसी सामान भारत-नेपाल सीमा पर बिल का किया है

SC ने गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में दिए निर्देश

NEW DELHI: शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में सुनीता यादव और उनके दो पुत्रों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पीड़िता परिवार की शिकायत पर निष्पक्ष और उचित तरीके से जांच करने का निर्देश दिया है. जस्टिस एजी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इसके बाद उसके परिवार को धमकियां मिलने लगीं. कोर्ट ने पीड़िता परिवार की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं.

फर्जी डिग्री मामले में कर्मचारी निलंबित

NEW DELHI: नगर निगम की सभी में गुरुवार सभागार में कर्मचारी केशरीन चौधरी और अध्यापिका देने के आरोप में कर्मचारी रमेश मुखेडकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आरोप है कि उसने फर्जी डिग्री के आधार नगरी सेवक नहरी दस्तावेज प्रस्तुत किए. जिलाधिकारी ने मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है.

ट्रेन शौचालय में मिला युवक का शव

NEW DELHI: दक्षिण-नवलखा एक्सप्रेस की एसी चार बोगी के शौचालय में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. युवक टिकट के सहारे लखना मिला, लेकिन उसकी सफलता 58 सब नहीं हो सकी है. जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. युवक के बाल कोई चोटिल पाए, संघातन या हिंसा नहीं मिला. पुलिस पहचान के लिए मोबाइल जब्त की है.

स्टेम सेल थेरेपी पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

NEW DELHI: अटिपिकल मेडिकल विश्वविद्यालय के हवाला ने स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने पूछा है कि पहले दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं.

पूर्वोत्तर रेलवे
ई-निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्यों के लिये सुलगाव 'खुली निविदा' वार्षिक व्यवहार नियमन एवं मुलवाधान इलेक्ट्रिकल, मुख्यालय गोरखपुर, सक्षमता में द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से आमन्त्रित की जाती है:-
• निविदा सूचना संख्या 43 वर्ष 2026, वर्ष का विवरण: 0000/ब्रि/खुली/ के संख्या ए 0.Single सर्विसिंग मोटरों के संचार, कार्य की मात्रा, कार्य अवधि की सूचित के साथ सूचना अनुमानित लागत ₹ 1623.47.00, अमानत राशि ₹ 20,800/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0.00, कार्य समाप्त अवधि (30 दिन)।
(i) निविदाओं के बंद होने की अंतिम दिनांक एवं समय: 21-08-2026 को 13.00 बजे।
नोट: इस निविदा से सिलह्न पेडुलम आपन लोकेशन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार प्रपत्रन नहीं प्राप्त किया जाएगा। निम्नलिखित वेबसाईट पर देखा जा सकता है: www.ireps.gov.in की देखें।
जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे
ई-निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्यों के लिये ई-निविदा भरे मंडल विद्युत इंजीनियर / टीआरडी, मुरादाबाद रेलवे, संबलपुर के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से आमन्त्रित की जाती है:-
क्रम सं. 1, निविदा सं. एनबिद/टीआरडी/आरए-आईटी-216, कार्य का विवरण: मुरादाबाद रेलवे के अंतर्गत मण्डल में MVSR, NT, PSPS, INCRA, RZA, DNOY, BWT और LWR क्षेत्रों पर इन पैकेजेस पोजीशनों को उप लोको के उड़ी-लोको उप लोको कार्यों के संचार संबंधित कार्यों / ई-ऑफिस कार्य हेतु की दिये जिले के लगभग 28.08.2026 से 31.08.2026 के 13:00 बजे तक ई-निविदा खुलने की तिथि व समय 28.08.2026 को 13.30 बजे, अनुमानित लागत ₹ 42,34,328.83, बयाना राशि-₹42,300/-, निविदा शुल्क ₹ 0.00, कार्य समाप्ति की अवधि-90 माह।
नोट: (i) इस निविदा के विस्तृत विवरण आदान महोत्सव नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त निविदाओं को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
(ii) विस्तृत विवरण व निविदा प्रपत्र आदि हेतु कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट https://www.ireps.gov.in की देखें।
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी
मुरादाबाद/विद्युत-220 मुरादाबाद

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.o. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India
नीलामी सूचना

उ० प्र० लोक सेवा आयोग
प्रेस-विज्ञप्ति
सीधी भर्ती के संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत विज्ञप्ति पर विवरण विवरण निम्नवत है:-

S.No.	Advt. No.	Deptt. Name	Post Name	Deptt. No.
1.	D-4-E-1-2025	UP Public Service Commission Prayagraj	System Analyst	S-10/02

अतः यह दी जाकरकार में अभिरुचि अभ्यर्थियों से आवेदन सह ऑट-ऑफिस ऑफ प्रयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर दिनांक 30.07.2026 से 06.08.2026 तक उपलब्ध रहेंगे। इस आवेदनीय-प्रपत्र को ऑट-ऑफिस ऑफ आवेदनीय/प्रमाण पत्र भी उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से आवेदन पर दिनांक 30.07.2026 से 06.08.2026 तक ऑट-ऑफिस ऑफ आवेदनीय/प्रमाण पत्र करायी हैं। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि अंतर दीक्षी भर्ती के परिणाम से संबंध में सूचना का उल्लिखन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।
संख्या- 02/सी.आर./परा-10/2026-28 (सुनील विक्रम)
दिनांक: उपलब्धता, 28 जुलाई, 2026 उप सचिव।

पूर्वोत्तर रेलवे
निविदा सूचना संख्या
ई-निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्यों के लिये सुलगाव 'खुली निविदा' वार्षिक व्यवहार नियमन एवं मुलवाधान इलेक्ट्रिकल, मुख्यालय गोरखपुर, सक्षमता में द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से आमन्त्रित की जाती है:-
• निविदा सूचना संख्या 43 वर्ष 2026, वर्ष का विवरण: 0000/ब्रि/खुली/ के संख्या ए 0.Single सर्विसिंग मोटरों के संचार, कार्य की मात्रा, कार्य अवधि की सूचित के साथ सूचना अनुमानित लागत ₹ 1623.47.00, अमानत राशि ₹ 20,800/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0.00, कार्य समाप्ति की अवधि (30 दिन)।
(i) निविदाओं के बंद होने की अंतिम दिनांक एवं समय: 21-08-2026 को 13.00 बजे।
नोट: इस निविदा से सिलह्न पेडुलम आपन लोकेशन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार प्रपत्रन नहीं प्राप्त किया जाएगा। निम्नलिखित वेबसाईट पर देखा जा सकता है: www.ireps.gov.in की देखें।
जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग
विज्ञप्ति
सीधी भर्ती के संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत विज्ञप्ति पर विवरण विवरण निम्नवत है:-

Sr.	Advt. No.	Deptt.	Post Name	Deptt. No.
1	D-4-E-1-2025	DIRECTORATE OF CULTURE UTTAR PRADESH REGIONAL ARCHIVES OFFICER		S-03-05

उपर्युक्त पद के संबंधित के समस्त अभ्यर्थी के आवेदन हेतु आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर दिनांक- 31 जुलाई, 2026 से 06 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। उक्त अभ्यर्थी अपने ऐच्छिकतम आईडी / ओटी आदि एवं जानकारियों के आधार पर आवेदन अंक आवेदनीय / प्रपत्र का प्रयास कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि अंतर दीक्षी भर्ती के परिणाम के संबंध में सूचना का उल्लिखन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।
संख्या- 30(i)/सा./वीक्षा/एस-3/2026-16 टीसीपी-30 सुनील कुमार
दिनांक: उपलब्धता, 30 जुलाई, 2026 [उप सचिव]

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग
सूचित-विज्ञप्ति
लखनऊ सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ई-5/ई-1/2025 द्वारा वैज्ञानिक परिचर दायरण नहरविभाग नहरविभाग 2026 के अन्तर्गत सीट आवेदनों पर हेतु मानकतरता के संबंधित सूचना निम्नवत हैं :-

क्रम सं.	विज्ञापन संख्या	विषय	रिक्तता संख्या	पद का नाम	मानकतरता की तिथि व समय	नहरों की संख्या
1	ई-5/ई-1/2025	परिचर (दायरण/ नहरविभाग)	एस-04/01	परिचर (एकेडमी)	दिनांक 06.08.2026 प्रातः 10.00 बजे से।	01

उक्त मानकतरता के संबंध में विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।
संख्या- 01/दिप्रा/ए-4/2026-26 (सचिव कुमार सिंहदीप)
दिनांक- उपलब्धता, 30 जुलाई, 2026 उप सचिव।

